



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030]
No. 1030]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2008/आषाढ़ 31, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2008/ASADHA 31, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.आ. 1757(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यजीव), वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	सदस्य
3.	सचिव, सुन्दरवन कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	सदस्य
4.	सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकाता	सदस्य
5.	श्री सोमनाथ भट्टाचार्य, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय अध्यक्ष एवं नमभूमि प्रबंधन संस्थान	सदस्य
6.	डॉ. शैलेश नायक, निदेशक, आई एन सी ओ आई एस, हैदराबाद	सदस्य
7.	प्रो. सिद्धार्थ बेहुरा, प्रो-वाइस चांसलर, जाधवपुर विश्वविद्यालय	सदस्य

8	प्रो० सुब्रत मैती बीज विज्ञान और प्रौद्योगिक में प्रोफेसर कृषि संकाय, बी सी के वी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल	सदस्य
9	डा० एस पी सिन्हा राय संयोजक, आर्सेनिक टास्क फोर्स इन पश्चिम बंगाल और अध्यक्ष, फ्लोराइड टास्क फोर्स इन पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
10	मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	सदस्य

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात:-

- (i) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;
- (ii) (क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते कि इस उप-पैरा II के उपखंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि पश्चिम बंगाल की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं।
- IX. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें।
- XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे।
- XII. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा।
- XIII. कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा।

[फा. सं. 12-8/2005-आईए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**ORDER**

New Delhi, the 21st July, 2008

S.O. 1757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|---|----------|
| 1. Principal Secretary,
Department of Environment,
Government of West Bengal, Kolkata-1. | Chairman |
| 2. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife),
Department of Forests,
Government of West Bengal, Kolkata -1. | Member |
| 3. Secretary,
Department of Sundarban Affairs,
Government of West Bengal,
Bidhannagar, Kolkata-91 | Member |
| 4. Member Secretary,
West Bengal Pollution Control Board, Kolkata -91. | Member |
| 5. Shri Somnath Bhattacharyya,
Scientist,
Institute of Environmental Studies and Wetland Management.
Kolkata-98 | Member |
| 6. Dr. Shailesh Nayak,
Director,
Indian National Center For Ocean Information Services,
Hyderabad – 55. | Member |
| 7. Prof. Subrata Maity,
Professor in Seed Science and Technology,
Faculty of Agriculture, BCKV, Kalyani, West Bengal. | Member |
| 8. Prof. Siddhartha Behura,
Pro-Vice Chancellor,
Jadavpur University.
Kolkata -32 | Member |

9. Dr. S. P. Sinha Roy, Member
Convenor, Arsenic Task Force in West Bengal and
Chairman, Fluoride Task Force,
Government of West Bengal, Kolkata -1.
10. Chief Environment Officer, Member-Secretary
Department of Environment,
Government of West Bengal,
Kolkata-1.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of West Bengal, namely:—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the West Bengal State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor;

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and if found necessary reterring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organization;

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act, cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii)(a) of paragraph II of this Order;

- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the West Bengal State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area - specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and approval.
- VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal.
- IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XII. The Authority shall have its headquarters at Kolkata.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-8/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.आ. 1758(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार, केरल	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, केरल सरकार, अथवा उसका नामिती	सदस्य
3.	सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल सरकार, अथवा उसका नामिती	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार, अथवा उसका नामिती	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार, अथवा उसका नामिती	सदस्य
6.	सचिव, मत्स्य उद्योग विभाग, केरल सरकार अथवा उसका नामिती	सदस्य
7.	अध्यक्ष, केरल सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम	सदस्य

9	निदेशक, एकीकृत तटीय जोन, प्रबंधन केन्द्र, स्कूल ऑफ मेरीन साइंस, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	सदस्य
10	डा० मधूसूदन कुरुप स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल फिशरीज, सी यू एस ए टी, कोचीन	सदस्य
11	श्रीमती जे. मर्सीकुट्टी अम्मा, अस्वथी वेलिमोन पो०आ० कोलम जिला केरल	सदस्य
12	सदस्य सचिव, केरल सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, केरल	सदस्य सचिव

॥ प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात:-

(ii) केरल राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन / संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्विना बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते इस उप-पैरा ॥ के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ॥ के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे केरल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं का विरचना करेगा ।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा iv, v और vi के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- VIII. प्राधिकरण, केरल की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में यथानिर्धारित सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
- IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- X. प्राधिकरण को पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन होंगे ।
- XI. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुवनन्तपुरम में स्थित होगा ।
- XII. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

[फा. सं. जे-17011/26/2007-आई ए-III (भाग)]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2008

S.O. 1758(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|---|----------|
| 1. Principal Secretary,
Science and Technology Department,
Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala-33. | Chairman |
| 2. Principal Secretary,
Local Self Government,
Government of Kerala,
Thiruvananthapuram, Kerala-33 or his nominee. | Member |
| 3. Secretary,
Environment Department,
Government of Kerala,
Thiruvananthapuram, Kerala-33 or his nominee. | Member |
| 4. Principal Secretary,
Industries Department,
Government of Kerala,
Thiruvananthapuram, Kerala-33 or his nominee. | Member |
| 5. Principal Secretary,
Revenue Department,
Government of Kerala
Thiruvananthapuram, Kerala-33 or his nominee. | Member |
| 6. Secretary,
Fisheries Department,
Government of Kerala
Thiruvananthapuram, Kerala-33 or his nominee. | Member |
| 7. Chairman,
Kerala State Pollution Control Board,
Government of Kerala. Thiruvananthapuram, Kerala-33. | Member |
| 8. Director,
Centre for Earth Science Studies,
Thiruvananthapuram, Kerala-33. | Member |

- | | |
|---|------------------|
| 9. Director,
Centre for Integrated Management of Coastal Zones,
School of Marine Science,
Cochin University of Science and Technology,
Cochin, Kerala-22. | Member |
| 10. Dr. Madhusoodhana Kurup,
School of Industrial Fisheries,
Cochin University of Science and Technology,
Cochin, Kerala-22. | Member |
| 11. Smt. J. Mercykutty Amma,
Aswathy, Vellimon, P.O.Kollam District, Kerala -13. | Member |
| 12. Member Secretary,
Kerala State Council for Science,
Technology and Environment,
Thiruvananthapuram, Kerala-33. | Member Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Kerala, namely :—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Kerala State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Kerala, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Kerala.
- IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

- X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XII. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.
- XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No. J-17011/26/2007-IA-III (Pt.)]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.आ. 1759(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए उड़ीसा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

1	सरकार के प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार,	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ बस्तिया, अध्यक्ष, समुद्र तट सुरक्षा परिषद्, उड़ीसा, डोलामण्डप साही, पुरी-752001,	सदस्य
3	डॉ० बी.आर. सुब्रामनियन परियोजना निदेशक, एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन, महासागर विकास विभाग, चैन्नई,	सदस्य
4	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा,	सदस्य
5	डॉ० मनमोहन मोहंती, भू-विज्ञान के पूर्व एमिराइट्स प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर,	सदस्य
6	डा० प्रताप कुमार मोहंती, रीडर, समुद्र विज्ञान बेरहामपुर विश्वविद्यालय,	सदस्य

7	सरकार के आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास विभाग, उड़ीसा सरकार,	सदस्य
8	सरकार के प्रधान सचिव, मत्स्यपालन और पशु संसाधन विकास विभाग, उड़ीसा सरकार,	सदस्य
9	अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा , भुवनेश्वर,	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिल्का विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर	सदस्य
11	मुख्य कार्यकारी, उड़ीसा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, भुवनेश्वर,	सदस्य
12	मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भुवनेश्वर,	सदस्य
13	निदेशक, सरकार के पर्यावरण एवं विशेष सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार,	सदस्य -सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात:-

(vii) उड़ीसा राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;

(viii) (क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते कि इस उप-पैरा II के उपखंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।

- (iii) आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना ।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे उड़ीसा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि उड़ीसा की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं ।
- IX. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें ।
- XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे ।
- XII. प्राधिकरण का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा ।
- XIII. कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा ।

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2008

S.O. 1759(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Orissa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Principal Secretary to Government, Forest and Environment Department, Government of Orissa, | Chairman |
| 2 | Sri Jagannath Bastia, President Beach Protection Council of Orissa, Dolamandap Sahi, Puri- 752001, | Member |
| 3 | Dr B.R. Subramanian, Project Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, Department of Ocean Development, Chennai, | Member |
| 4 | Chief Wildlife Warden,
Government of Orissa, | Member |
| 5 | Dr Manmohan Mohanti, Former Emeritus Professor in Geology, Utkal University, Bhubaneswar, | Member |
| 6 | Dr Pratap Kumar Mohanty, Reader in Marine Science, Berhampur University, | Member |
| 7 | Commissioner-cum-Secretary to Government, Urban Development Department, Government of Orissa, | Member |
| 8 | Principal Secretary to Government, Fisheries and Animal Resources Development Department, Government of Orissa, | Member |
| 9 | Chairman,
State Pollution Control Board,
Orissa, Bhubaneswar, | Member |

10	Chief Executive, Chilika Development Authority, Bhubaneswar,	Member
11	Chief Executive, Orissa Remote Sensing Application Centre, Bhubaneswar	Member
12	Chief Conservator of Forests, Regional Office, Ministry of Environment and Forests, Bhubaneswar,	Member
13	Director, Environment-cum -Special Secretary to Government, Forest and Environment Department, Government of Orissa.	Member Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Orissa, namely :—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Orissa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order;

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to the Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Orissa, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Orissa.

- IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XII. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar.
- XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No.J-17011/13/1999-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.आ. 1760(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	सरकार के सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, तमिलनाडु सरकार	अध्यक्ष
2.	निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, 807,, अन्ना सलान, चैन्नई-2	सदस्य
3.	संयुक्त आयुक्त (राजस्व प्रशासन) आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विभाग, चेपॉक, चैन्नई-5	सदस्य
4.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिंडी, चैन्नई-8	सदस्य
5.	सदस्य सचिव, चैन्नई मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण, एगमोर, चैन्नई-8	सदस्य
6.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राजाजी भवन, बसंतनगर, चैन्नई-90	सदस्य
7.	प्रो. आर. रमेश, निदेशक, समुद्र प्रबंधन संस्थान अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-25	सदस्य
8.	डॉ. एस. कोठीरोली,	सदस्य

	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पल्ली कारानई चैन्नई -02	
9	डा० टी बालासुब्रामन्यम निदेशक, सेन्टर फॉर एडवांसड स्टडी इन मैरीन बायोलॉजी, अन्नामलय विश्वविद्यालय पारांगीपीटिया-2, कुडालोर जिला तमिलनाडु	सदस्य
10	डा० के थानशेखरन निदेशक, सेन्टर फॉर एन्वायरमेंट स्टडीज अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	सदस्य
11	श्री के. कालीदासन फाउंडर, ओ एस ए आई एन्वायरमेंट आर्गेनाइजेशन	सदस्य
12	निदेशक, पर्यावरण तमिलनाडु सरकार, सैदपेठ, चैन्नई-15	सदस्य-सचिव

॥ प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात:-

- (i) तमिलनाडु राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन / संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;
- (ii) (क) उक्त अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्विध बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते इस उप-पैरा ॥ के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे तमिलनाडु राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं का विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तमिलनाडु की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में यथानिर्धारित सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण को पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय चैन्नई में स्थित होगा।

XII. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

[फा. सं. 12-8/2005-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2008

S.O. 1760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|--|----------|
| 1. Secretary to Government,
Environment and Forests Department,
Government of Tamil Nadu. Chennai-9. | Chairman |
| 2. Director, Town and Country Planning Department,
Government of Tamil Nadu, 807, Anna Salai, Chennai-2. | Member |
| 3. Joint Commissioner (Revenue Administration),
Disaster Management and Mitigation Department,
Government of Tamil Nadu, Chepauk, Chennai-5. | Member |
| 4. Member Secretary,
Tamil Nadu Pollution Control Board,
Guindy, Chennai-32. | Member |
| 5. Member Secretary,
Chennai Metropolitan Development Authority,
Egmore, Chennai-8. | Member |
| 6. Regional Director,
Central Groundwater Board,
Rajaji Bhawan, Besant Nagar, Chennai-90. | Member |
| 7. Prof. R. Ramesh,
Director,
Institute for Ocean Management,
Anna University, Chennai-25. | Member |
| 8. Dr. S. Kathirolu,
Director,
National Institute of Ocean Technology,
Pallikaranai, Chennai-02. | Member |
| 9. Dr. T. Balasubramanian,
Director,
Centre for Advanced Study in Marine Biology,
Annamalai University,
Parangipettai-02. Tamil Nadu. | Member |

- | | |
|--|------------------|
| 10. Dr. K. Thanasekaran,
Director,
Centre for Environment Studies,
Anna University, Chennai-25. | Member |
| 11. Thiru K. Kalidasan,
Founder, Organisation for Social Action and Improvement
(OSAI Environmental Organization). 4/C-34, Cheran Nagar,
G.N.Mills, Coimbatore -29. | Member |
| 12. Director, Department of Environment,
Government of Tamil Nadu,
Saidapet, Chennai-15. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Tamil Nadu, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Tamil Nadu State Government and specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;
- (ii)(a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
- (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization:

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraph (ii)(a) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Tamil Nadu State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Tamil Nadu.
- IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XII. The Authority shall have its headquarters at Chennai.
- XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-8/2005-IA-III]
Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'